AAE –1 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

अक्तूबर, 2011

सार लेखन, प्रारूप और व्यकरण

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

टिप्पणियां :

(1) सार और प्रारूप तैयार करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करते समय परीक्षार्थी द्वारा उन्हें समझने और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे छोटे वाक्यों में व्यक्त करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गद्यांश को चयनित रूप में दोहरा दे।

(2) इस प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न और 4 पृष्ठ हैं।

(3) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. निम्नलिखित लेखांश का सार लिखिए और उसे उपयुक्त शीर्षक दीजिए:-

अवसंरचना को सामान्यतः सुविधाओं के भौतिक ढांचे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से जनता को सामान और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अवसंरचना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जैसे कि परिवहन (रेलवे, सड़क, सड़क परिवहन, पत्तन और नागर विमानन), संचार (डाक और दूर-संचार सेवाएं) और अन्य जन कल्याण कार्य (जलपूर्ति एवं सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन)। यह उत्पादकता बढ़ाकर और जीवन की गुणता बढ़ाने वाली सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवाकर आर्थिक विकास में योगदान देती है। अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंध बहुविध और जटिल हैं। यह उत्पादन, खपत, वितरण, व्यापार आदि जैसे प्रत्येक आर्थिक कार्यकलाप को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के बाह्य प्रभाव होते हैं। किसी देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त अवसंरचना सुविधाओं का उपलब्ध होना अनिवार्य है।

विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद, भारत अनिवार्य सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना और सेवाओं की मांग और पूर्ति के बीच अभी भी भारी अंतर का सामना कर रहा है। अवसंरचना संबंधी कमियां भारत की आर्थिक वृद्धि और स्पर्धात्मकता को बनाए

रखने, गहन बनाने और विस्तार करने में भारी बाध्यकारी कमी सिद्ध हो रही हैं। अवसंरचना की कमी अर्थव्यवस्था और इसके लाभों के आंचलिक, क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक के विस्तार में अड़चन डाल रही है। पिछले दशक के तीव्र गति से हुए विकास का लाभ अधिकांश ऐसी जनता को नहीं मिला जो श्रम पर निर्भर कम कुशल और गावों में रहने वाली तथा कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्रों में कार्यरत है। ग्यारहवीं योजना ने विद्युत, सड़कों, पत्तनों, विमानपत्तों और रेलवे जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश के महत्व को पहचाना और ग्यारहवीं योजना के आधार वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5.6% से अंतिम वर्ष अर्थात् 2011-12 तक लगभग 9% तक इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाए जाने का प्रयास किया। कुछ क्षेत्रों जैसे कि दूर-संचार जिन्होंने प्रस्तावित से अधिक निवेश का उच्चतर स्तर प्राप्त किया, की वास्तविक उपलब्धि 8.5% के आसपास रहने की संभावना है जबकि अन्य क्षेत्रों की उपलब्धि काफी कम रही। ग्यारहवीं योजना में शुरु हुए कार्य को बारहवीं योजना में जारी रखना होगा जिसका लक्ष्य अवसंरचना में निवेश की दर को 2017-18 तक लगभग 10.5% बढ़ाना होना चाहिए। इसका अर्थ है कि अवसंरचना में निवेश जिसका ग्यारहवीं योजना अवधि में 500 बिलियन डालर का लक्ष्य रखा गया था उसे 2012-13 से 2017-18 तक की बारहवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 1 ट्रिलियन डालर तक बढ़ाना होगा। इससे दो मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक है, आवश्यकता के निवेश के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए और दूसरी है कार्यान्वयन संबंधी उन अड़चनों को कैसे दूर किया जाए जो इस समय परियोजना के पूरा होने में विलंब कर रही हैं।

जहां तक वित्तपोषण का संबंध है, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधन कम पड़ेंगे और जैसा कि ऊपर देखा गया है, इन संसाधनों की पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए जोकि सब को शामिल कि जाने के लिए अत्यावश्यक है और इस समय इन्हें कम धनराशि उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना दूसरी प्राथमिकता है। प्रक्षेपित निवेश आवश्यकताओं को सरकार के बजट संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। सुधार किए जाने की गुंजाइश सार्वजनिक वित्त की स्थिति को देखते हुए सीमित है। संघ और राज्य सरकारों का संयुक्त घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। सरकारें मनमाने ढंग से उधार नहीं ले सकती क्योंकि उनकी उधार लेने की सीमा को राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से नियंत्रित किया गया है। अतः केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों को ऐसी अवसंरचना नीति अपनानी चाहिए जिसमें सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक- निजी भागीदारी दोनों शामिल हों। सार्वजनिक निवेश को उन क्षेत्रों की ओर उन्मुख करना होगा जहां निजी क्षेत्र के आने की सम्भावना न हो जबकि शेष अवसंरचना का यथासम्भव विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाए। इस क्षेत्र में कीमती अनुभव प्राप्त हुए हैं और

सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का ढांचा बनाने के लिए प्रक्रिया संबंधी बहुत सी प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है। हमें यह अनुभव लेते रहना आवश्यक है और ऐसा नवीन प्रयास शुरू करना चाहिए जिसमें अवसंरचना निवेश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका को जोकि ग्यारहवीं योजना में लगभग 30% थी बारहवीं योजना में 50% तक बढ़ाना होगा।

अवसंरचना विकास में दूसरी बड़ी चुनौती कार्यान्वयन से संबंधित है। अवसंरचना परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयों और जहां भूमि अधिग्रहण कर लिया गया होता है वहां अधिक्रमण पर कार्रवाई करने और अन्य उपयोगिताओं के साथ समन्वय की कमी जैसी अन्य कठिनाइयों के कारण अक्सर विलम्ब हो जाता है। वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों द्वारा भी परियोजनाएं रूक जाती हैं। वनों और पर्यावरण की सुरक्षा निश्चित रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है परन्तु वर्तमान प्रक्रियाएं अक्सर पर्याप्त पारदर्शी नहीं होती और अनिश्चित भविष्य वाली होती है। तथापि, परियोजना विकासकर्ता भी दोषमुक्त नहीं होते। वे पर्यावरण संबंधी विनियमों को लागू करने में ढील बरतने के आदि होते हैं और उनमें स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व पर्यावरण संबंधी विनियमों या अधिनियम की अनदेशी करने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि वे यह मानते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों को बाद में नियमित किया जा सकता है। हमें ऐसी प्रणाली अपनानी होगी जिसमें अधिक पारदर्शिता, भविष्यसूचकता हो और साथ ही जिसे भविष्य में दृढ़तापूर्वक लागू किया जा सके। इस प्रक्रिया में हमें चालू परियोजनाओं की समस्याओं पर तर्कसंगत रूप से कार्रवाई करने के तरीके ढूंढने की आवश्यकता है जबकि भविष्य के लिए बेहतर प्रणालियां स्थापित करनी होंगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आगामी वर्षों में आने वाली इन कठिनाइयों की ओर गम्भीर रूप से ध्यान देना होगा।

यह अर्थव्यवस्था भारी भरोसे के वातावरण में बारहवीं योजना अवधि में प्रवेश करेगी परन्तु वह बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करने वाली भी होगी। सकल घरेलू उत्पाद की गति को बढ़ाकर 9% या इसके आसपास करने के लिए जो अधिकांश कार्य किए जाने की आवश्यकता है वह नजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा परन्तु एक ऐसा नीति परिवेश उपलब्ध कराने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी जो निवेशकों के अनुकूल हो और समावेशन वृद्धि में सहायक हो। सरकार के अपने संसाधनों को प्राथमिकता की स्पष्ट भावना से नियोजित करना होगा। इस संदर्भ में, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जल प्रबंधन एवं ग्रामीण अवसंरचना तथा अवसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्य अवसंरचना क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों दोनों द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। बड़ी परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर किया जाना चाहिए। (1083 शब्द)

(25 अंक)

2. उपर्युक्त लेखांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए):
   (i) देश के विकास में अवसंरचना का महत्व।
   (ii) अवसंरचना विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की प्रासंगिकता।
   (iii) उपर्युक्त लेखांश से भारत में अवसंरचना विकास में कठिनाई के क्षेत्रों की पहचान कीजिए।
   (15 अंक)

3. "मीडिया" सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में लिखिए)
   (25 अंक)

4. महालेखा नियंत्रक की ओर से भारत सरकार के सभी सचिवों को भेजे जाने वाले अर्ध-शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उनके मंत्रालयों में विभिन्न योजना स्कीमें लागू किए जाने के लिए कार्यनिष्पादन जांच का महत्व बताया गया हो।
   (20 अंक)

5. निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। (कोई पांच)

1. कृतज्ञ	2. वाचाल	3. उष्ण
4. तटस्थ	5. महात्मा	6. संधि

   (5 अंक)

6. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए (कोई पांच)

1. आंखों से गिरना	2. कमर टूटना
3. गर्दन पर सवार होना	4. निन्यानवे के फेर में पड़ना
5. रंगा सियार होना	6. पारा उतरना
7. मुट्ठी गरम करना	

   (5 अंक)

7. निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक-एक शब्द लिखें - (कोई पांच)

1. जिसका हृदय विशाल हो	2. बुराई के लिए प्रसिद्ध
3. दूसरों के दोष ढूंढने वाला	4. जिसकी कोई इच्छा न हो
5. जो किसी कला में कुशल हो	6. युद्ध में स्थिर रहने वाला
7. जिसकी गिनती आगे वालों में होती हो।	

   (5 अंक)

AAE – 1 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

OCTOBER, 2011

PRECIS AND DRAFT

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

Note : 1. While evaluating the question on precis and drafting the candidates would be evaluated for their understanding and ability to express the same in short sentences using simple words. He would not be expected to reproduce the passage selectively.
2. This question paper contains **7** questions and **4** pages.
3. All the questions are **compulsory**.

1. **Write a precis of the following passage and give suitable title**

Infrastructure is generally defined as the physical framework of facilities through which goods and services are provided to the public. The infrastructure sector covers a wide range of services such as transportation (railways, roads, road transportation, ports, and civil aviation), communications (postal and tele-communications services), and other public goods (water supply and sanitation, solid waste management, urban transport). It contributes to economic development by increasing productivity and by providing amenities that enhance the quality of life. Its linkages to the economy are multiple and complex. It affects each of the economic activities such as production, consumption, distribution, trade, etc directly or indirectly having both the positive and negative externalities. The availability of adequate infrastructure facilities is imperative for the overall economic development of a country.

Despite becoming the growing economy of the world, India continues to face large gaps in the demand and supply of essential social and economic infrastructure and services. The infrastructure shortages are proving to be the leading binding constraint in sustaining, deepening, and expanding India's economic growth and competitiveness. Lack of infrastructure is preventing the sectoral, regional and socioeconomic broadening of the economy and its benefits and is affecting inclusive growth in India. The benefits of accelerated growth of

the last decade have not been shared by large sections of the population which are labor dependent, low skilled, rural based and working in agriculture and manufacturing sectors. The Eleventh Plan recognized the importance of investing more in infrastructure sectors such as power, roads, ports, airports, and railways, and sought to raise investment in these sectors from about 5.6% of GDP in the base year of the Eleventh Plan 2006-07 to around 9% by the last year, i.e. 2011-12. The actual achievement is likely to be around 8.5% with some sectors, e.g. telecommunications, achieving higher levels of investment than projected, while others achieved significantly less. The task begun in the Eleventh Plan has to continue in the Twelfth Plan, which should aim at increasing the rate of investment in infrastructure to around 10.5% by 2017-18. This implies that investment in infrastructure, which has targeted at $500 billion in the Eleventh Plan period, would have to increase to about $1 trillion over the Twelfth Plan period 2012-13 to 2017-18. This poses two major challenges. One is how to finance the investment needed, and the second is how to overcome implementation hurdles, which currently delay project completion.

As far as financing is concerned, it is clear that public sector resources will be scarce and, as noted above, the first priority for these resources must be education and health, which are crucial for inclusiveness and are currently underfunded. Critical infrastructure in rural areas and backward areas is another priority. The projected investment requirements cannot be met from government's budgetary resources. The scope for making improvements is limited by the state of public finances. The combined deficit of the Union and State governments is around 10% of GDP. Governments can also not borrow arbitrarily, since their borrowing has been capped through the Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act. Both the Central and State governments must therefore follow an infrastructure strategy which consists of a combination of public investment and public-private partnership (PPP). Public investment would have to be directed to areas where the private sector is unlikely to come, with the rest of infrastructure being developed as far as possible through PPP. Valuable experience has been gained in this area and many of the teething problems related to procedures for structuring PPP projects have been overcome. We need to build on this experience and launch a renewed effort in which the role of PPP in infrastructure investment may have to increase from around 30% in the Eleventh Plan to as much as 50% in the Twelfth Plan.

The second major challenge in infrastructure development relates to implementation. Infrastructure projects are often delayed due to difficulties in land acquisition, and where land has been acquired, due to other difficulties

such as dealing with encroachments and lack of coordination with other utilities. Projects are also held back by difficulties in obtaining forest and environmental clearance. Protecting forest and the environment is obviously an extremely important objective, but the current processes are often not sufficiently transparent and predictable. However, project developers are not without blame. They have got used to laxity in application of environmental regulations and there is a tendency to ignore environmental regulations or act in anticipation of clearances in the belief that such actions can be regularized later. We need to move to a system with much greater transparency, predictability and also tighter enforcement in future. In the process we may need to find ways of dealing with the problems of ongoing projects in a reasonable manner while establishing better systems for the future. Both the Central government and the State governments have to give serious attention to resolving these problems in the years ahead.

The economy will enter the Twelfth Plan period in an environment of great promise but also one that presents major challenges. Much of what needs to be done to accelerate GDP growth to 9% or so will be done by the private sector, but the Central and State governments have a crucial role to play in providing a policy environment that is seen as investor friendly and is supportive of inclusive growth. The government's own resources have to be deployed with a clear sense of priority. In this context, health, education and critical infrastructure development, especially water management, rural infrastructure, and infrastructure development in backward areas must have top priority. For other infrastructure areas, the maximum use must be made of PPPs both by the Central government and by the States. Impediments in the implementation of large projects should be speedily removed. (954 words)

(25 marks)

2. **Answer the following questions based on the passage above (the answer should be in approx. 50 words each):** *(15 marks)*

   (i) The importance of infrastructure in the development of the country.

   (ii) Mention the relevance of Public Private Partnership (PPP) in the infrastructure development.

   (iii) From the passage above, identify the problem areas in infrastructure development in India.

3. **Media can play an important role of mediator between Government and Public Comment. (around 150 words)** *(25 marks)*

4. **Draft a DO letter from Controller General of Accounts to all the Secretaries to the Govt. of India highlighting the significance of Performance Audit in the successful implementation of various Plan Schemes in their Ministries.** *(20 marks)*

5. **(a) Change the following sentences (simple) into complex sentences:** *(3 marks)*

   (i) A lost moment is lost forever.

   (ii) Healthy persons have no need of the physicians.

   (iii) In the absence of the cat, the mice will play.

   (b) Correct the following sentences *(2 marks)*

   (i) He told me that you have left school a year ago.

   (ii) The sceneries of the Himalaya mountains are wonderful.

6. **Fill in the blanks with appropriate prepositions :** *(5 marks)*

   (i) You are liable _____ disciplinary action if you do not comply _____ orders.

   (ii) _____ of my repeated advice, he indulged ____ unnecessary arguments with the boss.

   (iii) I prevailed _____ him to join our office.

   (iv) Everywhere there seems _____ be a feeling that the world is moving _____ disaster which cannot be prevented.

   (v) This judgement also dwells _____ other interesting aspects _____ the I.T. Act and I.T. Rules.

7. **Make sentences to bring out differences in meaning of the following words (any five)** *(5 marks)*

(i)	Conscious	:	Conscientious
(ii)	Contagious	:	Contiguous
(iii)	Descent	:	Dissent
(iv)	Emigrant	:	Immigrant
(v)	Expedient	:	Expeditious
(vi)	Righteous	:	Riotous
(vii)	Statue	:	Statute